

# दैनिक विश्व परिवार

● अंक : 238 ● वर्ष : 11 ● रायपुर, गुरुवार 14 मार्च 2024 ● पृष्ठ : 08 ● मूल्य : 3 रुपए ● संस्थापक : कीर्तिशेष- श्री कैलाश चन्द्र जैन

## संक्षिप्त समाचार

छत्तीसगढ़ को मिले 4 नये आईएएस अधिकारी रायपुर (विस)। छत्तीसगढ़ को मिले 4 नये आईएएस अधिकारी मिले हैं। राज्य सरकार ने लाल बहादुर शर्मा राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी से प्रतिशक्षण प्राप्त करने के बाद 2023 वैच के बार अधिकारियों का पोस्टिंग आदेश जारी किया है। जारी आदेश जारी किया है। राज्य आदेश जारी किया है। राज्य सरकार के अनुसार अनुपमा आबंद को रायपुर, एम भारव का दुर्ज, तब्दील ज्ञाना को विलासपुर तथा दुर्गा प्रसाद को जांजीरी चांपा में सहायता कलेक्टर के पद पर पदव्य किया गया है।

**सामरिक महत्व के रेयर अर्थ खनिज के एक्सप्लोरेशन लायसेंस के लिए नोटिस इनवाइटिंग टेंडर जारी**

रायपुर (विस)। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा आज मुख्यमंत्री निवास में आयोजित एक संक्षिप्त समारोह में कोंडांगांव, नारायणपुर और बस्तर जिले में डायरेंस तथा सामरिक महत्व के रेयर अर्थ खनिज के तीन ब्लॉक का ई-वीलाली के माध्यम से एक्सप्लोरेशन लायसेंस आबंदन के लिए इनवाइटिंग टेंडर जारी किया गया। संक्षिक्रम में उप मुख्यमंत्री श्री आरुण साव, खनिज विभाग के सचिव श्री पी दयानंद, सचालक भौमिकी एवं खानिकर्म श्री सुनील जैन सहित संवादी अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित हैं।

## कलेक्टर-एसपी कांफेंस : कलेक्टर-एसपी के कार्यों से ही सरकार की छवि बनती है : सीएम विष्णुदेव साय



रायपुर (विश्व परिवार)। मुख्यमंत्रीविष्णुदेव साय ने आज मुख्यमंत्री निवास कार्यालय से बैठियों कांफेंसिंग के जरिये कलेक्टर-एसपी कांफेंस लेकर सासन की योजनाओं और कानून व्यवस्था को लेकर आवश्यक निर्देश दिए। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि आज तीन महीने के बाद कलेक्टर-एसपी कांफेंस हो रही है। तीन महीने के भीतर ही निश्चय रूप से योग्य के सहस्रों से हमारी सरकार ने जनता के विश्वास के मुताबिक बहुत से काम किये हैं और मोदी जी की गारंटी को पूरा किया है। हमें और भी अच्छा काम करने की जरूरत है। जनता ने हमें विश्वास से बैठाया है, हमें जनता के विश्वास के मुताबिक बहुत से काम किये हैं और मोदी जी की गारंटी को पूरा किया है। हमें और भी अच्छा काम करने की जरूरत है। जनता ने हमें बहुत काम किया है, प्रधानमंत्री आवास योजना, बकाया धन का बोनस, धन की ब्यापर खरीदी, 21 किंवदं प्रति एकड़ 3100 की दर से, कल अंतर की राशि भी दे दिए। महाराष्ट्र बंदन योजना के तहत पहली किश्त की राशि भी जारी हो गई है। एक तरह से 3 महीने में हमें बहुत काम किया है।

मुख्यमंत्री साय और भीतर सरकार की बहुत काम किया है। ग्रामीण स्तर में पटवारी, आरआई द्वारा बंदनारा, नामांतरण का काम ब्यापर खरीदी, 21 किंवदं प्रति एकड़ 3100 की दर से, कल अंतर की राशि भी दे दिए। महाराष्ट्र बंदन योजना के तहत पहली किश्त की राशि भी जारी हो गई है। एक तरह से 3 महीने में हमें बहुत काम किया है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य शासन और भारत सरकार की बहुत योग्य योजना प्रेषण में संचालित है। सभी योजनाओं को प्रेषण की अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की आवश्यकता है, कलेक्टर आवश्यकता के बीचीकरण का कार्य शीर्ष पहुंचाने में काम किया गया है।

### प्रधानमंत्री आवास योजना में तेजी लाएं

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमारी सरकार ने 18 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना का पारा दिताहिण्यों को पिछले 5 साल में आवास निलाना था ऐसे मकान से वीचों ही जाए थे और जिनके पार कार्य अधूरा हैं जिसका कारण उन्हें जिला छात्रा के रूप पाला जाए। इस योजना की जिला स्तर पर जिनके राशन कार्ड के बीचीकरण का कार्य शीर्ष पहुंचाने की जाए। राशन कार्ड के बीचीकरण का कार्य शीर्ष पहुंचाने की जाए। इस योजना की जिला स्तर पर जिनके राशन कार्ड के बीचीकरण का कार्य शीर्ष पहुंचाने की जाए। इस योजना की जिला स्तर पर जिनके राशन कार्ड के बीचीकरण का कार्य शीर्ष पहुंचाने की जाए।

मुख्यमंत्री आवास योजना की जिला स्तर पर जिनके राशन कार्ड के बीचीकरण का कार्य शीर्ष पहुंचाने की जाए। इस योजना की जिला स्तर पर जिनके राशन कार्ड के बीचीकरण का कार्य शीर्ष पहुंचाने की जाए।

मुख्यमंत्री आवास योजना की जिला स्तर पर जिनके राशन कार्ड के बीचीकरण का कार्य शीर्ष पहुंचाने की जाए।

मुख्यमंत्री आवास योजना की जिला स्तर पर जिनके राशन कार्ड के बीचीकरण का कार्य शीर्ष पहुंचाने की जाए।

मुख्यमंत्री आवास योजना की जिला स्तर पर जिनके राशन कार्ड के बीचीकरण का कार्य शीर्ष पहुंचाने की जाए।

मुख्यमंत्री आवास योजना की जिला स्तर पर जिनके राशन कार्ड के बीचीकरण का कार्य शीर्ष पहुंचाने की जाए।

मुख्यमंत्री आवास योजना की जिला स्तर पर जिनके राशन कार्ड के बीचीकरण का कार्य शीर्ष पहुंचाने की जाए।

मुख्यमंत्री आवास योजना की जिला स्तर पर जिनके राशन कार्ड के बीचीकरण का कार्य शीर्ष पहुंचाने की जाए।

मुख्यमंत्री आवास योजना की जिला स्तर पर जिनके राशन कार्ड के बीचीकरण का कार्य शीर्ष पहुंचाने की जाए।

मुख्यमंत्री आवास योजना की जिला स्तर पर जिनके राशन कार्ड के बीचीकरण का कार्य शीर्ष पहुंचाने की जाए।

मुख्यमंत्री आवास योजना की जिला स्तर पर जिनके राशन कार्ड के बीचीकरण का कार्य शीर्ष पहुंचाने की जाए।

मुख्यमंत्री आवास योजना की जिला स्तर पर जिनके राशन कार्ड के बीचीकरण का कार्य शीर्ष पहुंचाने की जाए।

मुख्यमंत्री आवास योजना की जिला स्तर पर जिनके राशन कार्ड के बीचीकरण का कार्य शीर्ष पहुंचाने की जाए।

मुख्यमंत्री आवास योजना की जिला स्तर पर जिनके राशन कार्ड के बीचीकरण का कार्य शीर्ष पहुंचाने की जाए।

मुख्यमंत्री आवास योजना की जिला स्तर पर जिनके राशन कार्ड के बीचीकरण का कार्य शीर्ष पहुंचाने की जाए।

मुख्यमंत्री आवास योजना की जिला स्तर पर जिनके राशन कार्ड के बीचीकरण का कार्य शीर्ष पहुंचाने की जाए।

मुख्यमंत्री आवास योजना की जिला स्तर पर जिनके राशन कार्ड के बीचीकरण का कार्य शीर्ष पहुंचाने की जाए।

मुख्यमंत्री आवास योजना की जिला स्तर पर जिनके राशन कार्ड के बीचीकरण का कार्य शीर्ष पहुंचाने की जाए।

मुख्यमंत्री आवास योजना की जिला स्तर पर जिनके राशन कार्ड के बीचीकरण का कार्य शीर्ष पहुंचाने की जाए।

मुख्यमंत्री आवास योजना की जिला स्तर पर जिनके राशन कार्ड के बीचीकरण का कार्य शीर्ष पहुंचाने की जाए।

मुख्यमंत्री आवास योजना की जिला स्तर पर जिनके राशन कार्ड के बीचीकरण का कार्य शीर्ष पहुंचाने की जाए।

मुख्यमंत्री आवास योजना की जिला स्तर पर जिनके राशन कार्ड के बीचीकरण का कार्य शीर्ष पहुंचाने की जाए।

मुख्यमंत्री आवास योजना की जिला स्तर पर जिनके राशन कार्ड के बीचीकरण का कार्य शीर्ष पहुंचाने की जाए।

मुख्यमंत्री आवास योजना की जिला स्तर पर जिनके राशन कार्ड के बीचीकरण का कार्य शीर्ष पहुंचाने की जाए।

मुख्यमंत्री आवास योजना की जिला स्तर पर जिनके राशन कार्ड के बीचीकरण का कार्य शीर्ष पहुंचाने की जाए।

मुख्यमंत्री आवास योजना की जिला स्तर पर जिनके राशन कार्ड के बीचीकरण का कार्य शीर्ष पहुंचाने की जाए।

मुख्यमंत्री आवास योजना की जिला स्तर पर जिनके राशन कार्ड के बीचीकरण का कार्य शीर्ष पहुंचाने की जाए।

मुख्यमंत्री आवास योजना की जिला स्तर पर जिनके राशन कार्ड के बीचीकरण का कार्य शीर्ष पहुंचाने की जाए।

मुख्यमंत्री आवास योजना की जिला स्तर पर जिनके राशन कार्ड के बीचीकरण का कार्य शीर्ष पहुंचाने की जाए।

मुख्यमंत्री आवास योजना की जिला स्तर पर जिनके राशन कार्ड के बीचीकरण का कार्य शीर्ष पहुंचाने की जाए।

मुख्यमंत्री आवास योजना की जिला स्तर पर जिनके राशन कार्ड के बीचीकरण का कार्य शीर्ष पहुंचाने की जाए।

मुख्यमंत्री आवास योजना की जिला स्तर पर जिनके राशन कार्ड के बीचीकरण का कार्य शीर्ष पहुंचाने की जाए।

मुख्यमंत्री आवास योजना की जिला स्तर पर जिनके राशन कार्ड के बीचीकरण का कार्य शीर्ष पहुंचाने की जाए।

मुख्यमंत्री आवास योजना की जिला स्तर पर जिनके राशन कार्ड के बीचीकरण का कार्य शीर्ष पहुंचाने की जाए।

मुख्यमंत्री आवास योजना की जिला स्तर पर जिनके राशन कार्ड के बीचीकरण का कार्य शीर्ष पहुंचाने की जाए।

मुख्यमंत्री आवास योजना की जिला स्तर पर जिनके राशन कार्ड के बीच



## मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में 160 जोड़े बंधे विवाह बंधन में

अतिथियों ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया साथ ही सुखी दार्पत्य जीवन की शुभकामना दी और उपहार भेंट किए

महासमुंद्र (विश्व परिवार)। महासमुंद्र के संजय कानन में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत पूरे विधि विधान से 160 जोड़े विवाह बंधन में बंधे। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष उषा पटेल, सांसद प्रतिनिधि संदीप दीवान, पार्षद देवीचंद राठी, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष पवन पटेल सहित प्रतिनिधिगण नवविवाहित दम्पतियों को आशीर्वाद दिया साथ ही सुखी दम्पत्य जीवन की शुभकामना दी और उपहार भेंट किए। विवाह कार्यक्रम में संबंधित विभाग के अधिकारी-कर्मचारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहित परिजन मौजूद थे। ज़िला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास समीर पाण्डे ने बताया कि आज मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में 160 जोड़े विवाह बंधन में बंधे। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत गरीब परिवारों की लड़कियों की शादी के लिए राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता के रूप में 50 हजार



रूपए का अनुदान सहायता राशि प्रदान किया जाता है। प्रति जोड़ा 50 हजार रूपए का व्यय किया गया है। इसमें प्रत्येक कन्या को 21 हजार रूपए की

राशि बैंक खाते या बैंक ड्राफ्ट के रूप में प्रदान की जाएगी। इसके अलावा 15 हजार रुपए की राशि के उपहार दिए गए हैं। विवाह आयोजन व्यवस्था और परिवहन पर प्रति कन्या 8 हजार रुपए, इसके साथ वर-वधु के कपड़े, श्रृंगार सामग्री पर 6 हजार रुपए व्यय किया गया है।

## तीन दिवसीय योगाभ्यास प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम का शुभारंभ

**सूरजपुर(विश्व परिवार)** | छत्तीसगढ़ योग आयोग रायपुर द्वारा जिला सूरजपुर के शिव मन्दिर प्रांगण भटगांव में 03 दिवसीय योगाभ्यास प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि महिला बाल विकास एवं समाज कल्याण विभाग मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजबाड़े जी द्वारा किया गया। कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री एम.एल. पाण्डेय सचिव छत्तीसगढ़ योग आयोग एवं साथ ही विभिन्न संगठनों के सम्मानितजन, समाज के प्रमुखजन, व्यापारी संघों के प्रतिनिधि, स्थानीय पंचायत एवं नगरीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधि एवं विभिन्न प्रकार के महिला समूहों के प्रतिनिधि एवं अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। कार्यक्रम आयोजन में फ्लैक्स एवं बैनर लगाते हुए बाइक रैली के साथ रोड शो, गायत्री परिवार द्वारा महायज्ञ किया गया। कार्यक्रम में मंत्री के द्वारा योग किट का वितरण किया गया एवं भोजन की व्यवस्था भी किया गया। कार्यक्रम का आयोजन श्री गौरव कुमार देववांगन सहायक लेखाधिकारी छत्तीसगढ़ योग आयोग रायपुर एवं योग आयोग प्रबंधक श्री रविकान्त कुम्भकार के समन्वय से किया गया।

# लोकसभा चुनावः कोतवाली सहित चार थानों के लिए अब नए चेहरे की तलाश ठेका कर्मियों ने एसईसीएल कार्यालय का घेराव कर किया प्रदर्शन

कोरबा (विश्व परिवार)। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के प्रभावशील होने से ठीक पहले निर्वाचन आयोग के निर्देश पर दो वर्ष से अधिक समय से जिले में पदस्थ अधिकारियों को रेंज से बाहर भेजने का काम जारी है। पुलिस विभाग ने हाल में ही एक सूची जारी की। कोरबा जिले के चार निरीक्षक इसमें प्रभावित हुए हैं। इसके साथ विभाग में रिपर्मेंशन होना तथ्य है। कोतवाली सहित तीन थाना में किसे प्रभारी बनाया जाए इसके लिए माथापच्ची करनी पड़ रही है। पुलिस

मुख्यालय की ओर से जारी आदेश के अंतर्गत कोतवाली प्रभारी नितीन उपाध्याय और दीपक थाना प्रभारी अश्वनी राठौर को सुकमा स्थानांतरित किया गया है। जबकि बालकोनगर प्रभारी अभिनवकांत सिंह को बीजापुर व कुमुड़ा प्रभारी मनीष नागर को कांक्रे जिले में भेजा गया है। जबकि बस्तर क्षेत्र से ही मोती पटेल को कोरबा जिले में स्थानांतरित किया गया है। कोरबा जिले में निरीक्षकों की पर्याप्त पदस्थापना पहले से ही है। इनमें से कई रक्षित केंद्र में सेवाएं दे रहे हैं। अलग-अलग थाना से यहां जबकि लोचन चक्रवर्ती में 4 थानांतरित किये गए हैं है कि नवीन एक बार फिर द्वारा कोरबा परिवर्तन किया थानों के किये जा सकते हैं में कार्यरत हैं में काम कर सकता है। बालकोनगर

समय पर उन्हें  
वेजा गया है। अब  
सभा चुनाव के  
प्रभारियों को  
ने के आदेश जारी  
किए में माना जा रहा  
है दस्तावेज से पहले  
पुलिस विभाग के  
जिले में बड़ा  
जाएगा। इसमें  
भारी यहां से वहां  
हैं जबकि लाइन  
निरीक्षकों को मैदान  
का अवसर मिल  
कोतवाली और  
थाना सबसे

महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं इसलिए  
यहां सुलझे हुए निरीक्षक को  
बैठाने की नीति पर काम हो  
सकता है। इसके अलावा दीपका  
और कुसमुंडा कोयलांचल में  
आए दिन अलग-अलग कारण  
से उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों  
के महेनजर क्षमतावान अधिकारी  
की खोज की जा रही है जो वहां  
के हिसाब से न केवल कामकाज  
कर सके बल्कि समस्याओं का  
निवारण भी कर सके। सूत्रों ने  
बताया कि पुलिस विभाग के द्वारा  
निरीक्षक स्तर के अधिकारियों के  
तबादलों से संबंधित एक और  
सूची जारी की जानी है।

# ठेका कर्मियों ने एसईसीएल कार्यालय का घेराव कर किया प्रदर्शन

**कोरबा(विश्व परिवार)**। एसईसीएल के कोरबा मुख्यालय में पूर्व धोषणा अनुसार कोयला मजदूर पंचायत के बैनर तले सैकड़ों ग्रामीणों और ठेका कर्मियों ने लगभग 8 घंटे प्रदर्शन किया। मुख्यालय के मुख्य द्वार पर डटे ग्रामीणों ने कार्यालय का धेराव कर दिया। बड़ी संख्या में महिलाएं भी अपने छोटे-छोटे बच्चों के साथ प्रदर्शन में शामिल हुईं। कोयला मजदूर पंचायत के केन्द्रीय उपाध्यक्ष गजेन्द्र पाल सिंह तंबर ने बताया कि स्टारएक्स मिनिरल्स कंपनी द्वारा मजदूरों का शोषण किया जा रहा है। 16 सूत्रीय मांगों में सभी मजदूरों को एचपीसी वेतनमान से जोड़कर पे-स्लीप प्रदान करना, हाईपावर कमेटी द्वारा बढ़े हुए वेतनमान का एरियर के साथ भुगतान, जनवरी माह के वेतन में चालकों के हाजिरी में फर्जी कटौती की जांच, प्रत्येक माह के 10 तारीख को सभी मजदूरों के वेतन भुगतान की मांग शामिल है। उन्होंने कहा कि सभी मजदूरों की 26 दिनों की ड्यूटी सुनिश्चित की जाए। साथ ही मजदूरों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी कंडम हो चुकी गाड़ियों की जांच कराई जाए, ताकि भविष्य में किसी मजदूर के साथ अनहोनी न हो। आंदोलन व कई बैठकों के बाद भी शोषण का क्रम जारी है जिसे लेकर एक दिवसीय आंदोलन किया गया। करीब 8 घण्टे तक चले प्रदर्शन के बाद भी एसईसीएल का कोई भी अधिकारी चर्चा के लिए नहीं पहुंचा जिससे आक्रोशित कामगारों व ग्रामीणों ने 13 मार्च को सराईपाली खदानबंदी का ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि मंगलवार को इस संबंध में पुलिस-प्रशासन को ज्ञापन सौंपा जाएगा।

## विकासखंड नवागढ़ के ग्राम पंचायत खोखरा में आजीविका ऋण मेला का हुआ आयोजन

जांजगीर-चांपा(विश्व परिवार)। कलेक्टर श्री आकाश छिकारा ने मंगलवार को नवागढ़ विकासखंड के ग्राम पंचायत खोखरा के मनका दाई मंदिर प्रांगण में लगाये गये आजीविका ऋण मेला में शामिल हुए। इस दौरान कलेक्टर ने उपस्थित हितग्राहियों को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि इसके माध्यम से आप दूसरों को भी रोजगार प्रदान कर सकते हैं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को ग्रामीणों को सक्षम बनाने और स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने कहा। साथ ही महिलाओं को योजना की जानकारी देते हुए आजीविका गतिविधियों से जोड़ने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए हैं। आजीविका ऋण मेला में 749 54 लाख का

# रात में रिहायशी इलाके तक पहुंचा हाथियों का झुंड घर को तोड़ा, बुजुर्ग दंपती को कुचलकर मार डाला

रखने की हिदायत दी है। मिली जानकारी के मुताबिक प्रतापपुर वन परिक्षेत्र के ग्राम पंचायत दरहोरा में यह घटना हुई है। हरिधन (79 वर्ष) और उसकी पत्नी नन्ही (65 वर्ष) जंगल किनारे घर बनाकर रह रहे थे। रविवार की रात हाथियों ने कच्चे मकान को तोड़ दिया। डरकर दोनों घर से बाहर निकल आए और हाथियों को देख भागने लगे। हाथियों ने दोनों सूँड से उठाकर पटक दिया और पैरों से कुचल दिया। हाथियों ने घर के अंदर रखे अब्बाज को

गया गए। चीख-पुकार और हाथियों के चिंचाड़ की आवाज सुनकर आसपास के लोगों ने शोर मचाया। इसके बाद हाथी पास के ही जंगल में घुस गए। सुबह सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम गांव महुंची। ग्रामीणों ने वन अमले पर हाथियों की मौजूदगी की सूचना नहीं देने का आरोप लगाया। वन विभाग ने मृतक के परिजनों को 25-25 हजार की तत्काल सहायता राशि उपलब्ध कराई है। मुआवजा प्रकरण भी बनाया जा रहा है। वन विभाग के स्वस्थ अशोष

भगत ने बताया कि बुजुर्ग दंपती को मारने वाले दो दौतैल हाथियों में एक हाथी सीतापुर लुंझ से अंबिकापुर होते हुए प्रतापपुर पहुंचा है। दूसरा दौतैल वाइफ्जगर क्षेत्र में विचरण कर रहे 34 हाथियों के दल से अलग होकर प्रतापपुर आया है। करीब 15 दिनों से हाथी गणेशपुर, सिंधरा और सरहरी के जंगल में विचरण कर रहे थे। वन विभाग ने ग्रामीणों को सतर्क रहने और जंगल के तरफ नहीं जाने की हिदायत दी है।

सुनालिया नहर पुल पर नहीं लगेगा जाम, बेहतर आवागमन के साथ मिलेगा आराम

**श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन की अनुशंसा पर वाई शेप अंडरपास की मिली स्वीकृति**

## **फ्लेक्टर अजीत वसंत ने दी प्रशासकीय स्वीकृति**



**कोरबा(विश्व परिवार)** । शहर में प्रवेश के साथ ही रेल्वे स्टेशन आने-जाने वाले सुनालिया नहर पुल मुख्य मार्ग में रेल्वे क्रॉसिंग बंद होने की वजह से नहर पुल पर वाहनों के जाम में फँसने वाले आम लोगों को जल्दी ही राहत के साथ आराम मिलने लगेगा । आम लोगों को फटक बंद होने से इस मार्ग पर आवागमन में जो परेशानी उठानी पड़ती है, वह आने वाले समय में दूर हो जाएगी । कोरबा के विधायक और छत्तीसगढ़ शासन के उद्योग, वाणिज्य एवं श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन की पहल, अनुशंसा और कलेक्टर श्री अजीत वसंत के प्रयासों से इस सुनालिया रेल्वे क्रॉसिंग पर शीघ्र ही वाई शेप

अंडरपास का निर्माण होने वाला है। कलेक्टर द्वारा अंडरपास निर्माण के लिए 30 करोड़ 97 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति जल्दी उपरा प्रक्रिया

औद्योगिक नगरी वाले जिले के रूप में पहचान रखने वाले कोरबा जिले के हृदय स्थल पाँवर हाउस मुख्य मार्ग तथा सुनालिया नहर पुल मार्ग से शहरवासी नियमित आवागमन करते हैं। शहर से रेल्वे स्टेशन की ओर जाने और रेल्वे स्टेशन से शहर की ओर आने के लिए सुनालिया रेल्वे क्रॉसिंग का मार्ग महत्वपूर्ण स्थान है। विगत समय से सुनालिया नहर पुल वाले मुख्यमार्ग पर यातायात का दबाव भी तेजी से बढ़ रहा है। मुख्य मार्ग पर यातायात का दबाव बढ़ने से नहर पुल पर आये दिन ट्रैफिक जाम की स्थिति भी निर्मित होती है। यह समस्या और भी विकराल हो जाती है, जब कोई उत्सव का माहौल हो तथा रेल्वे फटक बंद हों। रेल्वे फटक के बंद होने व खलने के दौरान दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग जाती हैं। शहर की इस बड़ी समस्या को संज्ञान में लेकर कलेक्टर श्री अजीत वसंत द्वारा जिले के एसपी तथा अन्य अधिकारियों के साथ जिले में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने सुनालिया मार्ग सहित अन्य महत्वपूर्ण मार्गों का अवलोकन भी किया गया था। इस दौरान कलेक्टर ने लोक निर्माण विभाग (सेतु) के अधिकारियों को सुनालिया रेल्वे क्रॉसिंग में अंडरपास निर्माण के लिए स्टीमेट बनाने के निर्देश दिए थे। आखिरकार उद्योग मंत्री श्री देवांगन की अनुशंसा पर जिला खनिज न्यास मद से लगभग 30 करोड़ 97 लाख रुपए की लागत से अंडरपास निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

# संपादकीय किसानों के लिए सरकार की अहम पहल

## कहने की ज़रूरत पड़ी!

ડા. જયંતીલાલ ભંડારી

टिप्पणियां साधारण इस लिहाज से हैं कि किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में- जहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार हो- इन्हें कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। मगर आज हालात ऐसे हैं कि ऐसे मामले सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बीते हफ्ते दो साधारण बातें कहीं, लेकिन वो अखबारों में प्रमुख सुर्खियां बनीं। ये टिप्पणियां साधारण इस लिहाज से हैं कि किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में- जहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार हो- इन्हें कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। मगर आज देश के हालात ऐसे हैं कि ऐसे मामले सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाते हैं और अंततः कोर्ट को संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या करनी पड़ती है। पहली टिप्पणी संविधान के अनुच्छेद 370 को रद्द करने की आलोचना से संबंधित थी। एक प्रोफेसर ने इस कदम की आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि जिस रोज ये कदम कदम उठाया गया, वह एक काला दिन था। दूसरी टिप्पणी पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस पर उसे बधाई दिए जाने से संबंधित थी। कोर्ट ने कहा कि किसी दूसरे देश को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देने के पीछे दुर्भावना की तलाश नहीं की जानी चाहिए। कोर्ट ने कहा- ‘हर भारतीय नागरिक को जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को रद्द करने की आलोचना करने का अधिकार है। जिस रोज ये अनुच्छेद रद्द किया गया, उसे काला दिन बताना प्रतिरोध की भावना और रोष की अभिव्यक्ति है। अगर राज्य की हर आलोचना या प्रतिरोध को धारा 153-ए के तहत अपराध ठहराया जाएगा, तो लोकतंत्र- जो संविधान की अनिवार्य विशेषता है- टिक नहीं पाएगा।’ कोर्ट ने अपनी दूसरी टिप्पणी में कहा कि पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को कोई भारतीय नागरिक शुभकामना देता है, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। यह सद्भावना का इजहार है। वह नागरिक किसी खास मजहब से संबंधित हो, इसलिए ऐसी अभिव्यक्ति के पीछे दुर्भावना की तलाश नहीं की जानी चाहिए। जाहिर है, अभियुक्त मुस्लिम थे, जिन पर सांप्रदायिक द्वेष फैलने का इल्जाम लगा दिया गया था। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है। लेकिन आज ऐसी घटनाएं इक्का-दुक्का भर नहीं हैं। और ऐसे मामले में इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ता है, यही आज के सूरत-ए-हाल को बताता है।



करोड़ों लोगों की खाद्य सुरक्षा और आजीविका की होनी चाहिए। वस्तुतः खाद्य सुरक्षा एवं सार्वजनिक भंडारण के लिए भारत सरकार गेंहूं और चावल मेटे अनाज को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की पहले से तय कीमत पर खरीदती है और फिर उन्हें गरीबों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिये सस्ते दाम या मुफ्त में वितरित करती है। यह खाद्य सुरक्षा भूख से त्रस्त लाखों लोगों को भूख से बचाने का सरकार का नीतिगत तरीका है। यह भारत के द्वारा वर्ष 2030 तक देश में भूख व गरीबी मिटाने के लक्ष्य से जुड़ा मुद्दा भी है। ज्ञातव्य है कि वर्तमान में डब्ल्यूटीओ के नियमों के मुताबिक 1986-88 के मूल्यों को आधार मानते हुए उत्पादन मूल्य का 10 प्रतिशत से अधिक किसानों को सब्सिडी नहीं दी जा सकती है। भारत इसमें बदलाव चाहता है ताकि किसानों को अधिक सब्सिडी देने पर वैश्विक मंच पर उसका विरोध नहीं हो सके। अमरीका सहित कई विकसित राष्ट्र खाद्यान्न के लिए भारत में दिए जा रहे एमएसपी कार्यक्रम पर सवाल उठा रहे हैं, उनका कहना है कि इस पर दी जा रही सब्सिडी डब्ल्यूटीओ व्यापार नियमों के तहत स्वीकृत सीमा से करोब तिगुनी हो गई है। ज्ञातव्य है कि वर्ष 2013 में बाली में हुए मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में सार्वजनिक भंडारण और खाद्य सुरक्षा को लेकर एक पीस क्लॉज पर हस्ताक्षर किए गए थे जिसके तहत अन्न भंडारण कार्यक्रम का स्थायी हल नहीं निकलने तक किसी भी देश के द्वारा अनाज की खरीददारी और उसे कम दाम पर लोगों को देने का विरोध नहीं किया जाएगा। भारत को आशंका है कि खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम पर रोक लगाई जाएगी तो इससे देश के करोड़ों लोगों की भूख, करोड़ों किसानों की आजीविका और भारतीय कृषि के भविष्य पर असर पड़ सकता है। इसी कारण भारत खाद्य सब्सिडी की सीमा तय करने का फॉर्मूला बदलने की मांग कर रहा है। निश्चित रूप से इस समय जब भारत 142 करोड़ से अधिक जनसंख्या के साथ दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन चुका है, देश में अभी भी 15 करोड़ से अधिक लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं और भारत को कुपोषण की समस्या से ग्रसित देश के रूप में रेखांकित किया जा रहा है, तब भारत में खाद्य सुरक्षा, अधिक खाद्यान्न उत्पादन और खाद्यान्न भंडारण की जरूरत बनी हुई है इस परिप्रेक्ष्य में सरकार के सराहनीय प्रयास दिखाइ भी दे रहे हैं। जहां सरकार डब्ल्यूटीओ सहित अन्य

विश्विक मंचों पर किसानों को अधिक समर्थन को न्यायसंगत बताती है, वहाँ हाल ही में 24 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लांच की गई दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के तहत अगले पांच साल में 1.25 लाख करोड़ रुपए की लागत से 700 लाख टन अनाज की भंडारण क्षमता के हजारों गोदाम बनाए जाएंगे। खास बात यह है कि अब कम्प्यूटरीकृत पैक्स को गोदाम तैयार करने, कस्टर हायरिंग सेंटर बनाने, उचित मूल्य की दुकानों की प्रक्रिया में तथा प्रसांस्करण इकाइयां तैयार करने जैसी बहुआयामी भूमिका में शामिल किया गया है। नई खाद्यान्न भंडार योजना वस्तुतः देश में भंडारण के बुनियादी ढांचे की कमी के कारण किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। नई विश्वाल भंडारण क्षमता के बाद किसान अपनी उपज को गोदामों में रखने, इसके बदले संस्थागत ऋण प्राप्त करने और बाजार मूल्य लाभकारी होने पर अपने खाद्यान्न को बेचने में सक्षम होंगे नई खाद्यान्न भंडार योजना का मकसद देश की खाद्य सुरक्षा को मजबूत करना, भंडारण क्षमता में कमी के कारण किसानों को फसल पैदावार के मौसम में कम मूल्य पर की जाने वाली बिक्री से होने वाले नुकसान से बचाना भी है। इस समय देश का खाद्यान्न उत्पादन लगभग 3200 लाख टन से भी अधिक है, जबकि भंडारण क्षमता कुल उत्पादन का केवल 47 प्रतिशत ही है। ऐसे में निश्चित रूप से तेजी से बढ़ता हुआ खाद्यान्न उत्पादन अब किसानों के परम्परागत खाद्यान्न भंडारों और सरकार की खाद्यान्न संग्रहण क्षमताओं को लांघते हुए चुनौतीपूर्ण बन गया है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि पिछले एक दशक में सरकार के विभिन्न कृषि योजनाओं के द्वारा छोटे किसानों और कृषि विकास को जिस तरह समर्थन मिला है, उससे कृषि उत्पादन लगातार बढ़ता गया है और खाद्यान्न भंडारण की आवश्यकता बढ़ती गई है। यद्यपि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादक देश है, लेकिन खाद्यान्न भंडारण में अभी भी बहुत पीछे है।

# विचार

## भारत अब डेमोक्रेसी नहीं?

वी-डेम के 179 देशों के सूचकांक में भारत को 104वें पायदान पर रखा गया है। संस्था के मुताबिक 2013 के बाद भारत में तानाशाही प्रवृत्ति तेजी से बढ़ी है। वह उन 10 देशों में शामिल हो गया है, जहां ये प्रवृत्ति सबसे तेजी से बढ़ी है। अंतरराष्ट्रीय संस्था - वेराइटी ऑफ डेमोक्रेसीज (वी-डेम) ने दोहराया है कि भारत अब लोकतंत्र नहीं है। उसने भारत को निर्वाचित अधिनायकतंत्र की श्रेणी में 2018 में ही रख दिया था। उसके बाद से वी-डेम के सूचकांक में भारत का दर्जा और गिरा ही है। इस बीच लोकतंत्र की सूरत पर रिपोर्ट तैयार करने वाली अमेरिकी संस्था फीडम हाउस भारत को आजाद देशों की श्रेणी से गिराकर उसे आंशिक आजादी वाले देशों की श्रेणी में रख चुकी है। वी-डेम ने इस वर्ष अपने सूचकांक में 179 देशों को शामिल किया है। उनके बीच भारत को 104वें पायदान पर रखा गया है। संस्था ने कहा है- 2013 के बाद भारत में तानाशाही प्रवृत्ति तेजी से बढ़ी है। इस तरह वह उन देशों में शामिल हो गया है, जहां हाल के समय में तानाशाही सबसे तेजी से बढ़ी है। इस रूप में भारतीय लोकतंत्र उस जगह पहुंच गया है, जहां 1975 में था- यानी जब देश में इमरजेंसी लागू हुई थी। वी-डेम ने कहा है कि इस समय दुनिया में तानाशाही प्रवृत्ति बढ़ने की लहर आई हुई है। यह प्रक्रिया 42 देशों में चल रही है, जहां को कुल आबादी दो अरब 80 करोड़ हैं- यानी जहां दुनिया की कुल आबादी का 35 प्रतिशत हिस्सा भारत में मौजूद है। भारत की वर्तमान सरकार ऐसी रिपोर्टों को तब्जो नहीं देती (या कम-से-कम वह ऐसा करने के संकेत ही देती है)। सार्वजनिक बयानों में वह इन्हें भारत विरोधी सोच से प्रेरित करार देती है। मगर यह बात अवश्य याद रखनी चाहिए कि भारत की पहचान अगर एक लोकतांत्रिक देश की बनी, तो वह उन पैमानों पर बेहतर सूरत की वजह से ही बनी, जिनको लेकर वी-डेम या फीडम हाउस जैसी संस्थाएं सूचकांक बनाती हैं। अब इन कसौटियों पर भारत का दर्जा गिर रहा है, तो इसके लिए उन संस्थाओं की कथित दुर्भावना को कारण मानना अतार्किक होगा। वैसे भी जो बातें वो संस्थाएं कह रही हैं, वैसा ही अनुभव बहुत सारे भारतवासियों का भी है।

## **भाजपा के इस दांव में खतरे भी**

लेकिन क्या भाजपा इस दांव में कामयाब हो पाएगी? कई बार इस तरह के दांव उलटे पड़ते हैं। कई बार कमज़ोर के प्रति सहानुभूति होती है। बिहार, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में तो डबल इंजन की डबल एंटी इन्कम्बेंसी हो सकती है। बिहार में जनता दल यू को साथ लेने के बाद भाजपा का पुरानी और छोटी सहयोगी पार्टियों से तालमेल बिगड़ा है क्योंकि उनको देने के लिए भाजपा के पास सीटें कम हैं। दूसरी ओर विपक्षी गठबंधन की पार्टियों में बेहतर तालमेल बना है। ध्यान रहे पिछली बार किशनगंज सीट पर मुकाबला इस वजह से था कि ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार को करीब तीन लाख वोट मिल गए थे। इस बार ऐसा होने की संभावना बहुत कम है। इसलिए किशनगंज सीट पर कांग्रेस या विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार के जीतने के चांस ज्यादा हैं। इसी तरह सीमांचल की अनेक सीटों पर और पिछली बार काटे की टक्रावाली यादव बहुल सीटों पर भी मुकाबला आसान नहीं है पप्पू यादव के साथ आने से सीमांचल का गणित अलग ढंग से बन रहा है। सीमांचल में पूर्णिया से लेकर अररिया, किशनगंज, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया, कटिहार तक पटना में पाटलिपुत्र और मगध में जहानाबाद जैसी सीटों पर काटे का मुकाबला है। झारखण्ड में सिंहभूम सीट पर कोड़ा परिवार की मदद से भाजपा ने अपनी स्थिति मजबूत की है लेकिन यह इस बात की गारंटी नहीं है कि वह पिछली बार की तरह 14 में से 12 सीट जीत जाए। पिछली बार तीन सीटों पर काटे की टक्राव हुई थी। लोहरदगा में कांग्रेस नौ हजार और खूंटी में डेढ़ हजार वोट से हारी थी। दुमका में शिवु सोरेन भी 30 हजार के करीब वोट से हारे थे। इन सीटों पर इस बार भाजपा के लिए लड़ाई आसान नहीं है। इसके अलावा लहर के बावजूद पिछले दोनों चुनावों में भाजपा राजमहल सीट नहीं जीत पाई। ऐसा लग रहा है कि चार से छह सीटों पर विपक्षी गठबंधन बहुत मजबूत है। शास्त्रीय राजनीति के नजरिए से देखें तो ओडिशा में भाजपा ने वह गलती की है, जो पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने और केरल में कांग्रेस व लेफ्ट मोर्चा ने नहीं की।

पंकज शर्मा

पिछले हफ्ते मैंने टीवी बहसों में भाजपा के हर प्रवक्ता से पूछा कि 12 लाख मतदान केंद्रों में से हर एक पर 370 अतिरिक्त वोट का मतलब क्या होता है, इसका हिसाब जानते हैं? क़रीब 44 करोड़ अतिरिक्त वोट। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को कुल मिला कर तकरीबन 23 करोड़ वोट मिले थे। उन में 44 करोड़ अतिरिक्त वोट जुड़ने का मतलब है कि 2024 में भाजपा के 67 करोड़ वोट। इसका अर्थ है कुल मतदान के 70 फ़ीसदी वोट भाजपा पाए। पिछले चुनाव में भाजपा को 37.7 प्रतिशत वोट मिले थे। तो क्या 2024 में उस के मतों में 32 फ़ीसदी का इजाफ़ा हो जाएगा? यह तो तथ्य है कि 2024 में नरेंद्र भाई मोदी अपनी भारतीय जनता पार्टी को 370 सीटों के आंकड़े पर नहीं पहुंचा पाएंगे। मगर इस से भी बड़ा सवाल यह है कि राहुल गांधी अपनी कांग्रेस को किस आंकड़े तक पहुंचा पाएंगे? ज़मीनी हालात ऐसे लग रहे हैं कि इन गर्भियों में स्पष्ट बहुमत के 272 अंक तक पहुंचने में भाजपा के पसीने छूट जाएंगे। मगर क्या धरती पर वे अंकुर फूट रहे हैं, जो इंडिया समूह को स्पष्ट बहुमत के अंक तक पहुंचा दें? मतदाताओं का बहुमत भले ही 'मोशा-भाजपा' के चंगुल से आज़ाद होने को छपटपा रहा हो, मगर क्या समूचे विषय और खासकर कांग्रेस की सांगठनिक तैयारियों में चुनाव-आरोहण की कोई ताब दिखाई दे रही है? यह तो साफ़ है कि नरेंद्र भाई भीतर-ही-भीतर घबराए हुए हैं। पिछले दो-तीन महीनों से उन की देह-भाषा में विचलन है और वे छँग साहस

में भाजपा को कुल मिला कर तकरीबन 23 करोड़ वोट मिले थे। उन में 44 करोड़ अतिरिक्त वोट जुड़ने का मतलब है कि 2024 में 67 करोड़ वोट। इस बार कुल 96 करोड़ मतदाता होंगे। उन में से 70 प्रतिशत वोट देने गए तो उन की तादाद होगी करीब 68 करोड़। तो क्या भाजपा को 68 में से 67 करोड़ वोट मिल जाएगा? मान लीजिए कि सौ प्रतिशत मतदान हो गया तो भी 67 करोड़ वोट पाने का मतलब होगा कुल मतदान के 70 फ़ीसदी वोट अपनी गठरी में बटोर ले जाना। पिछले चुनाव में भाजपा को 37.7 प्रतिशत वोट मिले थे। तो क्या 2024 में उस के मतों में 32 फ़ीसदी का इजाफ़ा हो जाएगा? जबका मैं खिसियानी हंसी थी और यह थोथा तर्क कि क्या हम एक बड़ा लक्ष्य तय करने का अधिकार भी नहीं रखते हैं? अब चूंकि नरेंद्र भाई के मुंह से एक बात निकल गई है तो भाजपा का कोइ प्रवक्ता आखिर कैसे हड्डबड़ी में हुई हिसाब की इस गड़बड़ी पर कोई टीका करे? सो, अनुचर बिना अकूल लगाए नारे लगा रहे हैं कि अब की बार 370 पार, अब की बार 400 पार, अब की बार फिर मोदी सरकार और-तो-और खुद नरेंद्र भाई भी अपने मुंह से हर जगह यही उद्घोष करते रहे हैं। दूसरों की आंखों में धूल झांकने के चक्र में खुद की आंखों में भी धूल झांकें के उपक्रम की इस बेचारगी पर मैं सहानुभूति-भाव से सराबोर होता जा रहा हूं। पराक्रम और सामर्थ्य के इस्पाती तरीं से बुरी बाह्य अचकन के भीतर से झांकित फटी बनियान का कातर-विलाप आप को सुनाई दे रहा हो, न दे रहा हो, मेरे मन में तो यह आवाज़ गहरी हूक पैदा कर रही है। सो, मैं तो पूरी तरह आश्वस्त होता

# विशेषाधिकार में घूस लेने की छूट नहीं....

अजोत द्विवेदी

सुप्रीम कोर्ट की सात जजों की संसदीय पीठ ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। चीफ जस्टिस डीवार्ड चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने बहुत दो टूक अंदाज में कहा है कि सदन के अंदर सांसदों को जो विशेषाधिकार मिले होते हैं उनमें रिश्त लेने की छूट शामिल नहीं है। अदालत ने कहा कि विशेषाधिकार इसलिए दिया गया है ताकि सांसद किसी भी विषय पर खुल कर अपनी राय रख सकें। बहस और विचार विर्मश में किसी तरह की बाधा नहीं आए, वह बेबाक हो, हर पहलू को समेटे हुए हो इसके लिए विशेषाधिकार का प्रावधान किया गया है। इस टिप्पणी के साथ ही सर्वोच्च अदालत ने 26 साल पहले हुई एक गलती को सुधार दिया। अदालत का यह फैसला दूरगामी असर वाल साबित होगा और इससे संसद के दोनों सदनों के साथ साथ राज्य विधानमंडलों की कार्यवाही को भी स्वच्छ, स्वतंत्र और पारदर्शी बनाने में मदद मिलेगी। अदालत के इस फैसले को समझने के लिए 1993 के जेएमएम रिश्त कांड और 1998 में आए फैसले के साथ साथ 2012 के मुकदमे के बारे में जानने की जरूरत है। तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव की अल्पमत सरकार पर आरोप लगे थे कि उसने 1993 में बहुमत साबित करने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसदों को रिश्त दी थी। पार्टी सुप्रीमो शिशु सोरेन सहित कई सांसद इसमें शामिल पाए गए थे। लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बेंच ने संविधान के अनुच्छेद 105 (2) और 194 (2) की व्याख्या करते हुए तीन-दो के बहुमत से फैसला सुनाया था कि संसद के अंदर सांसदों को हासिल विशेषाधिकार के तहत इस मामले में सांसदों



पर आपराधिक मुकदमा नहीं चल सकता है। तब से यह स्थित बनी हुई थी कि विशेषाधिकार के तहत रिश्त लेना भी शामिल है। यानी कोई सांसद या विधायक अगर रिश्त लेकर बोट करता है या सवाल पूछता है या बहस में हिस्सा लेता है तो उसके खिलाफ संसद या विधानसभा से बाहर मुकदमा नहीं चल सकता है। इतिहास कैसे त्रासदी के रूप में अपने को दोहराता है वह इस मामले में दिखा, जब 2012 के राज्यसभा चुनाव में शिवू सोरेन की बहू सीता सोरेन के ऊपर रिश्त लेकर निर्दलीय विधायक को बोट देने का आरोप लगा। जब उनके ऊपर मुकदमा कायम हुआ तो उन्होंने अपने समरु के मामले में आए 1998 के फैसले का हवाला दिया और अपने लिए मुकदमे से छूट मांगी। इसी मामले में 2014 से नए पिसे से 1998 के फैसले की समीक्षा शुरू हुई। पहले तीन जजों की बेंच ने सुनवाई की। फिर मामला पांच जजों की बेंच के पास गया और अंत में तय हुआ कि जब पहला फैसला पांच जजों की बेंच का है तो उससे बड़ी बेंच को इस पर विचार करना चाहिए ताकि स्पष्टता आ सके। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के अध्यक्षता में सात जजों की बेंच ने दो दिन यह मामला सुना और फैसला सुरक्षित रख लिया। अब अदालत ने एक राय से पुराने फैसले को पलट दिया है और कहा है कि धूस लेना विशेषाधिकार नहीं है। अदालत ने कहा है कि धूस लेना अपने आप में एक आपराधिक मामला है। धूस लेने के बाद इस बात का कोई मतलब नहीं रह जाता है कि आपने जिस काम के लिए धूस लिया वह काम किया या नहीं। अगर किसी सांसद ने बोट देने के लिए रिश्त ली है तो इससे मुकदमे की गुणवत्ता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि रिश्त लेने के बाद उसने बोट दिया या नहीं यह रिश्त देने वाले के हिसाब से उसने संसद में बात की या नहीं। रिश्त लेते ही अपराध का मामला बन जात है। सो, सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत स्पष्ट और दंटूक है। उम्मीद करनी चाहिए कि इससे संसद और राज्यों की विधानसभाओं की कार्यवाही पहले से

जा रहा हूं कि 2024 में ननेंद्र भाई की हुक्मत उन की मुट्ठी से फिसल रही है। लेकिन बावजूद इस के मैं इस पर आश्वस्त नहीं हो पा रहा हूं कि इंडिया-समूह के पर्वतारोही दनदनाते हुए रायसीना पहाड़ी की तरफ कूच कर चुके हैं। वे तो पिछले छह महीनों से बस हौले-हौले रेंगते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अगर मतदाताओं के मन में परिवर्तन की कोई बलवती इच्छा सुलग भी रही हो तो क्या उसे अखिल भारतीय शक्ति देना किसी राहुल गांधी, किसी शरद पवार, किसी लालू-तेजस्वी यादव, किसी अखिलेश यादव, किसी अरविंद केजरीवाल, आदि-आदि के लिए सुप्रकृति है? दक्षिण भारत, बंगाल, बिहार और पंजाब में बिखरे टापुओं पर अगर बदलाव का ध्वज फरफराने भी लगा तो क्या उस से ननेंद्र भाई इतने बेआबरू हो पाएंगे कि अपना झोला उठाएं और महफिल छोड़ कर चले जाएं? चलिए, मान लिया कि भाजपा 2019 की अपनी 303 सीटों में 67 की बढ़ोतरी कर उसे 370 पर पहुंचाने की स्थिति में नहीं है, मगर क्या कांग्रेस अपने 52 के आंकड़े को बढ़ा कर तीन अंकों तक पहुंचाने की कूवत रखती है? क्या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 5 से 25 या 15 पर पहुंच जाएगी? क्या समाजवादी पार्टी 5 से 20-25 पर पहुंच रही है? क्या राष्ट्रीय जनता दल को 25-30 सीटें मिल रही हैं? क्या तृणमूल कांग्रेस 22 के बजाय 32 सीटें अपने पछूं में बांध कर ले जाएगी? क्या आम आदमी पार्टी 15-20 का आंकड़ा छूती दिखाई दे रही है? क्या द्रुमुक की सीटें 24 से बढ़ कर 34 होने वाली हैं? क्या वाम दल दो दर्जन सीटें अपनी मुट्ठी में कर लेंगे?

## संक्षिप्त समाचार

## सम्बलपुर एवं पुणे के मध्य तीन फेरे के लिए होली स्पेशल ट्रेन की सुविधा

रायपुर (विश्व परिवार)। रेलवे द्वारा होली के अवसर पर सम्बलपुर-पुणे के मध्य यात्रियों में होने वाली भाईड़ की घटना में खत्म हुए एक होली स्पेशल सुपर फास्ट ट्रेन सम्बलपुर-पुणे-सम्बलपुर के मध्य तीन फेरे के लिये चलाई जायेगी एवं यह गाड़ी सम्बलपुर से 08327 नंबर के साथ तथा पुणे से 08328 नंबर के साथ चलेगी। 08327 सम्बलपुर-पुणे-होली स्पेशल सम्बलपुर से दिनांक 17, 24 एवं 31 मार्च, 2024 तथा 08328 पुणे-सम्बलपुर होली स्पेशल पुणे से दिनांक 19 एवं 26 मार्च तथा 02 अप्रैल, 2024 को छुटेगी। इस स्पेशल ट्रेन में 2 एस.एल.आर./एसएलआरडी, 06 सामान्य, 09, स्टीन, 04-एसी-01, 01 एसी-II सहित कुल 22 कोच रहेंगे। इस गाड़ी की विस्तृत सम्पर्क-सारणी निम्नानुसार है-

08327 सम्बलपुर-पुणे होली स्पेशल		08328 पुणे-सम्बलपुर होली स्पेशल	
पहुंच	छठ	पहुंच	छठ
—	22.00	सम्बलपुर	13.30 —
22.35	23.37	भारतीय रोड	12.45 12.47
23.35	23.40	भारतीय रोड	11.47 11.52
00.35	00.55	टिक्किलाप	10.35 10.55
01.35	01.45	कालामारी	09.50 10.00
02.35	02.37	खारियांगोर रोड	08.50 08.52
03.45	03.47	महाराष्ट्र रोड	08.00 08.02
04.40		लालगढ़ी	07.55
05.35	05.45	रायपुर	07.00 07.10
06.35	06.40	भुज	06.10 06.15
06.59	07.01	राजनगरीपाल	05.27 05.29
08.43	08.45	गोदावरी	04.04 04.06
10.50	10.55	वाराणसी	01.45 01.50
11.58	12.00	वर्धन	00.03 00.05
13.42	13.45	बंडोल	22.22 22.25
14.42	14.45	अकोला	20.37 20.40
16.45	16.50	भुवनेश्वर	18.15 18.20
19.05	19.10	मध्यप्रदेश	15.50 15.55
20.00	20.15	अकोला	14.15 14.17
23.03	23.05	अहमदाबाद	12.05
18.30	—	भुज	—
			19.00

## अमृतसर-कोरबा छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस का आगरा एवं वीरांगना लक्ष्मीबाई रेल मण्डल के अंतर्गत 12 रेलवे स्टेशनों की समय सारणी में आशिक परिवर्तन

रायपुर (विश्व परिवार)। रेलवे प्रशासन द्वारा रेल यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 18238 कोरबा-अमृतसर-कोरबा छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस का उत्तर मध्य रेलवे के वीरांगना लक्ष्मीबाई (झाँसी) एवं आगरा रेल मण्डल के अंतर्गत 12 रेलवे स्टेशनों की समय सारणी में आशिक परिवर्तन किया जा रहा है। उत्तर मध्य रेलवे के वीरांगना लक्ष्मीबाई (झाँसी) एवं आगरा रेल मण्डल के अंतर्गत 12 रेलवे स्टेशनों में गाड़ी संख्या 18237 कोरबा-अमृतसर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस की समय सारणी में आशिक परिवर्तन किया जा रहा है। गाड़ी समय सारणी की जानकारी इस प्रकार है-

गाड़ी संख्या	रेलवे स्टेशन	पहुंच	छठ
18237 कोरबा	आगरा	08.40	08.45
अमृतसर लक्ष्मीबाई	धौलकोपर जक्कन	09.58	10.00
एसप्रेस	मुंगेर	10.21	10.23
	गोदावरी	10.52	10.54
	डंडरा	11.28	11.30
	दीतांग	12.22	12.24
	बीरांगना लक्ष्मीबाई	13.20	13.28
	बंडोल	13.51	13.53
	बंडोल	14.04	14.05
	तालुकट्टे	14.17	14.19
	लक्ष्मीपुर	14.46	14.48
	धुंगी	15.08	15.10

## रामगंगमंडी सकल दिगंबर जैन समाज ने स्वरितभूषण माता जी को रामगंगमंडी आगमन हेतु निवेदन किया



रामगंगमंडी (विश्व परिवार)। परम पूज्य भारत गौरव गणिती आर्थिकी 105 स्वरितभूषण माताजी को रामगंगमंडी दिगंबर जैन समाज ने बवाला, पुर्ण युग मां को रामगंगमंडी आगमन हेतु निवेदन किया एवं एकल स्पर्धाकृति के अंतर्गत 12 रेलवे स्टेशनों में गाड़ी संख्या 18237 कोरबा-अमृतसर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस की समय सारणी में आशिक परिवर्तन किया जा रहा है। गाड़ी समय सारणी की जानकारी इस प्रकार है-

गोदी में पूज्य पंचायत के अध्यक्ष महासचिव रामगंगमंडी को गोदी संख्या 18237 कोरबा-अमृतसर-कोरबा छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस का उत्तर मध्य रेलवे के वीरांगना लक्ष्मीबाई (झाँसी) एवं आगरा रेल मण्डल के अंतर्गत 12 रेलवे स्टेशनों की समय सारणी में आशिक परिवर्तन किया जा रहा है। उत्तर मध्य रेलवे के वीरांगना लक्ष्मीबाई (झाँसी) एवं आगरा रेल मण्डल के अंतर्गत 12 रेलवे स्टेशनों में गाड़ी संख्या 18237 कोरबा-अमृतसर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस की समय सारणी में आशिक परिवर्तन किया जा रहा है। गाड़ी समय सारणी की जानकारी इस प्रकार है-

गोदी में पूज्य पंचायत के अध्यक्ष महासचिव रामगंगमंडी को गोदी संख्या 18237 कोरबा-अमृतसर-कोरबा छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस का उत्तर मध्य रेलवे के वीरांगना लक्ष्मीबाई (झाँसी) एवं आगरा रेल मण्डल के अंतर्गत 12 रेलवे स्टेशनों में गाड़ी संख्या 18237 कोरबा-अमृतसर-कोरबा छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस की समय सारणी में आशिक परिवर्तन किया जा रहा है। गाड़ी समय सारणी की जानकारी इस प्रकार है-

गोदी में पूज्य पंचायत के अध्यक्ष महासचिव रामगंगमंडी को गोदी संख्या 18237 कोरबा-अमृतसर-कोरबा छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस का उत्तर मध्य रेलवे के वीरांगना लक्ष्मीबाई (झाँसी) एवं आगरा रेल मण्डल के अंतर्गत 12 रेलवे स्टेशनों में गाड़ी संख्या 18237 कोरबा-अमृतसर-कोरबा छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस की समय सारणी में आशिक परिवर्तन किया जा रहा है। गाड़ी समय सारणी की जानकारी इस प्रकार है-

गोदी में पूज्य पंचायत के अध्यक्ष महासचिव रामगंगमंडी को गोदी संख्या 18237 कोरबा-अमृतसर-कोरबा छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस का उत्तर मध्य रेलवे के वीरांगना लक्ष्मीबाई (झाँसी) एवं आगरा रेल मण्डल के अंतर्गत 12 रेलवे स्टेशनों में गाड़ी संख्या 18237 कोरबा-अमृतसर-कोरबा छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस की समय सारणी में आशिक परिवर्तन किया जा रहा है। गाड़ी समय सारणी की जानकारी इस प्रकार है-

गोदी में पूज्य पंचायत के अध्यक्ष महासचिव रामगंगमंडी को गोदी संख्या 18237 कोरबा-अमृतसर-कोरबा छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस का उत्तर मध्य रेलवे के वीरांगना लक्ष्मीबाई (झाँसी) एवं आगरा रेल मण्डल के अंतर्गत 12 रेलवे स्टेशनों में गाड़ी संख्या 18237 कोरबा-अमृतसर-कोरबा छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस की समय सारणी में आशिक परिवर्तन किया जा रहा है। गाड़ी समय सारणी की जानकारी इस प्रकार है-

गोदी में पूज्य पंचायत के अध्यक्ष महासचिव रामगंगमंडी को गोदी संख्या 18237 कोरबा-अमृतसर-कोरबा छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस का उत्तर मध्य रेलवे के वीरांगना लक्ष्मीबाई (झाँसी) एवं आगरा रेल मण्डल के अंतर्गत 12 रेलवे स्टेशनों में गाड़ी संख्या 18237 कोरबा-अमृतसर-कोरबा छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस की समय सारणी में आशिक परिवर्तन किया जा रहा है। गाड़ी समय सारणी की जानकारी इस प्रकार है-

गोदी में पूज्य पंचायत के अध्यक्ष महासचिव रामगंगमंडी को गोदी संख्या 18237 कोरबा-अमृतसर-कोरबा छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस का उत्तर मध्य रेलवे के वीरांगना लक्ष्मीबाई (झाँसी) एवं आगरा रेल मण्डल के अंतर्गत 12 रेलवे स्टेशनों में गाड़ी संख्या 18237 कोरबा-अमृतसर-कोरबा छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस की समय सारणी में आशिक परिवर्तन किया जा रहा है। गाड़ी समय सारणी की जानकारी इस प्रकार है-

गोदी में पूज्य पंचायत के अध्यक्ष महासचिव रामगंगमंडी को गोदी संख्या 18237 कोरबा-अमृतसर-कोरबा छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस का उत्तर मध्य रेलवे के वीरांगना लक्ष्मीबाई (झाँसी) एवं आगरा रेल मण्डल के अंतर्गत 12 रेलवे स्टेशनों में गाड़ी संख्या 18237 कोरबा-अमृतसर-कोरबा छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस की समय सारणी में आशिक परिवर्तन किया जा रहा है। गाड़ी समय सारणी की जानकारी इस प्रकार है-

गोदी में पूज्य पंचायत के अध्यक्ष महासचिव रामगंगम



### व्यापार समाचार

#### शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया सीमित दायरे में रहा

मुंबई (एजेंसी)। रुपया मंगलवार को शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले सीमित दायरे में रहा। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने कहा कि प्रतिभागी अमेरिका में फरवरी के मुद्रास्पर्मिति के आंकड़ों और भारत में फरवरी के मुद्रास्पर्मिति के आंकड़ों तथा जनरी के आईआईपी आंकड़ों का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच, सकारात्मक घरेलू शेवर बाजार, विदेशी कोषों की आवक और विदेशी बाजार में अमेरिकी मुद्रा की कमज़ोरी से निवेशकों की भावना मजबूत हुई। दूसरी ओर कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों ने स्थानीय मुद्रा की बढ़त को सीमित किया। अंतर्वेंक विदेशी मुद्रा विनियम बाजार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 82.74 पर पहुंच गया। इस तरह रुपये ने पिछले बंद भाव के मुकाबले तीन ऐसे की बढ़त दर्ज की। रुपया सोमवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले आठ ऐसे की पिंगवट के साथ 82.75 पर बंद हुआ था। इस बीच, छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.06 प्रतिशत घटकर 104.80 पर पहुंच गया। वैश्विक तेल मानक ब्रेट कर्ड वायदा 0.36 प्रतिशत घटकर 82.51 अमेरिकी डॉलर प्रति बैल भाव पर था। शेवर बाजार के आंकड़ों के अनुसार विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने सोमवार को 4,212.76 करोड़ रुपये के शेवर खरीदे।

#### यात्री वाहनों ने फरवरी में अब तक की सबसे अधिक बिक्री दर्ज की

नईदिल्ली (एजेंसी)। भारत में यात्री वाहनों की थोक बिक्री फरवरी में सालाना आधार पर 11 प्रतिशत बढ़ी। उद्योग निकास सियाम ने मंगलवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि स्पैटेंट यूटीलिटी वाहनों (एप्स्ट्रीटी) की बाजार पर पकड़ बरकरार है। अंटोर्टी कंपनियों ने पिछले महीने डीलरों को कुल 3,70,786 यात्री वाहन भेजे, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में यह आंकड़ा 3,34,790 इकाई था। सियाम के महानिदेशक राजेश मेनन ने एक बयान में कहा, यात्री वाहनों ने इस साल फरवरी में अपनी अब तक की सबसे अधिक बिक्री दर्ज की। यह आंकड़ा फरवरी 2023 की तुलना में 10.8 प्रतिशत बढ़कर 3.7 लाख इकाई रहा। समीक्षाधीनी माह में कुल दोपहिया वाहनों की बिक्री 35 प्रतिशत बढ़कर 15,20,761 इकाई हो गई, जो पिछले साल इसी महीने में 11,29,661 इकाई थी। इसी तरह विदेशी वाहनों की थोक बिक्री फरवरी में 54,584 इकाई रही, जो पिछले साल समान माह में 50,382 इकाई थी। सोसाइटी ऑफ इंडिया औटोमोबाइल मैन्यूफैकरर्स (सियाम) के अध्यक्ष बिनोद अग्रवाल ने एक बयान में कहा कि पिछले साल के मुकाबले फरवरी 2024 में यात्री वाहनों, दोपहिया और तिपहिया वाहनों की बिक्री बढ़ी, जबकि वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री में थोड़ी गिरावट हुई।

#### होण्डा मोटरसाइकिल एण्ड स्कूटर इंडिया ने 2024 इंटरनेशनल रेसिंग चैम्पियनशिप के लिए अपने लाईनअप की घोषणा की

गुरुग्राम (एजेंसी)। भारतीय राइडरों को विश्वसरीय मंच पर प्रतिष्ठात हक्कने के प्रयासों को जारी रखने हुए होण्डा मोटरसाइकिल एण्ड स्कूटर इंडिया ने 2024 सीजन के लिए अपने इंटरनेशनल रेसिंग स्ट्रेंड का अनावरण किया। इंटरनेशनल रेसिंग स्ट्रिंग पर अपने क्रिकेट के प्रदर्शन के लिए तैयार, आईडीमिट्सु होण्डा रेसिंग इंडिया के चार राइडर, 2024 एफएसीएम एशिया रोड रेसिंग चैम्पियनशिप (एआरआरसी), थाईलैण्ड टैलेंट कप (टीटीसी) और एशिया टैलेंट कप (एटीसी) में एशिया के शीर्ष पायदान के प्रतिस्पर्धियों के साथ मुकाबला करेंगे। 2024 एआरआरसी सीजन के एपी250सीसी क्लास के लिए एकमात्र भारतीय दल - आईडीमिट्सु होण्डा रेसिंग इंडिया की टीम में प्रतिभाशाली युवा क्रिकेटर नियमित रूप से खेलती है, जो होण्डा इंडिया टैलेंट कप 2023 के मौजूदा चैम्पियन हैं। 2023 एआरआरसी में प्रतिस्पर्धा के बाद, वे 37 विश्वसरीय प्रतियोगितायों में 16वें स्थान पर हैं। उन्होंने एशिया टैलेंट कप 2023 के सैकड़ स्टर-अप मोहसीन पराम्बन होंगे, जिन्होंने 2023 एआरआरसी में होण्डा रेसिंग इंडिया का प्रतिनिधित्व किया और 37 प्रतियोगियों में 30वें स्थान पर रहे। एशियाई मंच पर उभयों भारतीय राइडरों को अपने कोशल प्रदर्शन एवं करियर के विकास के मार्ग प्रशस्त करते हुए, होण्डा रेसिंग इंडिया के उभयों तरीके से उत्तम रक्षण देवे 2024 एशिया टैलेंट कप और थाईलैण्ड टैलेंट कप दोनों में अपनी पहली इंटरनेशनल यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। उनकी लेखनीयता उल्लेखनीय में शामिल है - होण्डा इंडिया टैलेंट कप 2023 में प्लॉटर-स्टर-अप का खिलाफ व्यापार करना।

#### म्यूचुअल फंड में महिलाओं की बड़ी दिलचस्पी

नईदिल्ली (एजेंसी)। बात पैसे बचाने की हो तो महिलाओं को अधिकतर सुरक्षित निवेश या सेवांस का रुख करते देखा जाता है। लेकिन इस बीच महिलाओं ने बाजार में दिलचस्पी दिखाई दी है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडिया की मार्गे तो म्यूचुअल फंड में महिला निवेशकों की हिस्सेदारी मार्च 2017 में 15 प्रतिशत से बढ़कर दिसंबर 2023 में लगभग 21 प्रतिशत हो गई है। यानी कि महिला निवेशक अब म्यूचुअल फंड में निवेश को लेकर दिलचस्पी दिखा रही है। इस साल फरवरी में म्यूचुअल फंड में प्रबंधन के तहत कुल संपत्ति 50 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर गई, इसका कारण ये भी माना जा रहा है कि बड़ी संख्या में निषिय निवेशक बचत करने और ज्ञाता करने का टारेट बना कर म्यूचुअल फंड का रुख कर रहे हैं। एप्सी के आंकड़ों से एक और बात का बता चलता है कि विकास की यह गति इस अधिक के दौरान शहरी केंद्रों की तुलना में अधिक सित या अल्पविकसित केंद्रों में अधिक थी। बी-30 शहरों में महिला पोर्टफोलियो और संपत्ति की हिस्सेदारी क्रमशः 15 प्रतिशत से बढ़कर 18 प्रतिशत और 17 प्रतिशत से 28 प्रतिशत हो गई है।

## डब्ल्यूपीएल 2024 : गुजरात जायंट्स की यूपी वारियर्स पर 8 रन से जीत

नई दिल्ली (एजेंसी)। यहां के अरुण जेटली स्टेडियम में सोमवार को महिला प्रीमियर लीग के 18वें मैच में निचले पायदान पर रहने वाली गुजरात जायंट्स ने कड़े मुकाबले में यूपी वारियर्स को आठ रन से हराकर अपनी दूसरी जीत दर्ज की, जिससे वारियर्स की ओर लोअफ में जगह पड़ी करने की सभावनाएं धूमिल हो गई। वहां बलेजारी करने उत्तरी गुजरात जायंट्स ने कसान बेथ मूरी (52 गेंदों में 74 रन) के नावाद अधिक राउंड की मदद से, जबकि साथी सलामी बलेजार लौरा वोल्वाईट ने 30 गेंदों में 43 रनों की पारी खेली और शुरुआती मुकाबले आठ ऐसे की पिंगवट के साथ 82.75 पर बंद हुआ था। इस बीच, सकारात्मक घरेलू शेवर बाजार, विदेशी कोषों की आवक और विदेशी बाजार में अमेरिकी मुद्रा की कमज़ोरी से निवेशकों की भावना मजबूत हुई। दूसरी ओर कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों ने स्थानीय मुद्रा की बढ़त को सीमित किया।



जायंट्स नियमित अंतराल में विकेट पर 152 रन ही बना कैथरीन ब्राइस (11) दोहरे विकेट गंवाते हुए 20 ओवर में 8 सक। एशेले गार्डनर (15) और आंकड़े तक पहुंचने वाले गुजरात जायंट्स के अन्य बलेजार थे। सोमवी एकलोस्टेन (3-38) और दीपि शर्मा (2-22) ने पांच विकेट साझा किए। जीत और लोअफ में जगह बनाने के लिए 153 रनों का पीछा करते हुए यूपी वारियर्स की शुरुआत खारब रही। उन्होंने अपनी कसान एलिसा हीली (4), किण नवगिरे (0) और चमारी अथापथु (0) को जल्दी-जल्दी खीट दिया। दीपि शर्मा ने अकेले संभावकरते हुए 60 गेंदों में नौ चौकों और चार छक्कों की मदद से नावाद 88 रन बनाए और पूर्ण खेमनार (26 गेंदों में 36 रन) की मदद से नावाद 88 रन बनाए और पूर्ण खेमनार (26 गेंदों में 36 रन) की मदद से नावाद 88 रन बनाए और चार ओवर में 3-11 के अठ रन से हराया।

साथ गुजरात जायंट्स के लिए एकलोस्टेन (3-38) और दीपि शर्मा (2-22) ने पांच विकेट साझा किए। जीत और लोअफ में जगह बनाने के लिए 153 रनों का पीछा करते हुए यूपी वारियर्स की शुरुआत खारब रही। उन्होंने अपनी कसान एलिसा हीली (4), किण नवगिरे (0) और चमारी अथापथु (0) को जल्दी-जल्दी खीट दिया। दीपि शर्मा ने अकेले संभावकरते हुए 60 गेंदों में नौ चौकों और चार छक्कों की मदद से नावाद 88 रन बनाए और पूर्ण खेमनार (26 गेंदों में 36 रन) की मदद से नावाद 88 रन बनाए और चार ओवर में 3-11 के अठ रन से हराया।

## विश्व ओलंपिक मुक्केबाजी क्लालीफायर नार्डी ने विश्व नंबर-1 जोकोविच को हराकर बड़ा उलटफेर किया

बस्टो अर्मेजियो (एजेंसी)।

भारत के नियांत देव यहां पहले विश्व ओलंपिक मुक्केबाजी क्लालीफायर में पुरुषों के 71 किलो कार्टर फाइनल में 2021 विश्व चैम्पियनशिप के रजत पदक विजेता यूएसएप के ओमारी जोन्स से 1-4 से हार गए। पहले दो राउंड में 43 रनों की गति दर्ज की गयी। ओमारी ने लगातार अटेंट करते हुए 5-0 की अच्छी शुरुआत करने के लिए एप्ले राउंड में शुरुआती बोलोहेन (75 किलो) के साथ चार कोटा बालीना बोलोहेन (75 किलो) को खोला कर चुका है। जिन्होंने इंडियन वेल्स (एजेंसी) के राउंड अंत में राउंड में दो घंटे 17 मिनट में 6-4, 3-6, 6-3 से हाराकर सबको चौका दिया। पिछले हफ्ते नार्डी क्लालीफायर के अंतिम राउंड में दो घंटे 17 मिनट में राउंड अंत में डेविड गोफिन से ब्रेव राउंड में दो घंटे 17 मिनट में राउंड अंत में डेविड गोफिन से ब्रेव र

